The Research Dialogue

An Online Quarterly Multi-Disciplinary
Peer-Reviewed / Refereed Research Journal
ISSN: 2583-438X
Volume-2, Issue-1, April-2023
www.theresearchdialogue.com

राष्ट्रीय नई शिक्षा नीति 2020 और शिक्षाविदों का योगदान

कवता विश्नोई

सहायक प्रोफेसर
शिक्षाशास्त्र विभाग
डीजीपीजी कॉलेज, कानपुर

शोध सार:

यह शोध पत्र नई शिक्षा नीति 2020 के लिए संदर्भित है, जो मुख्यतः शिक्षा नीति 2020 की मुख्य विशेषताओं का वर्णन करने के साथ–साथ शिक्षाविदों का योगदान का उल्लेख भी करता है। नई शिक्षा नीति का उद्देश्य बिना किसी भेद भाव के प्रत्येक व्यक्ति को विकसित होने के लिए एक सामान अवसर प्रदान करना है तथा विद्यार्थियों में ज्ञान, कौशल, बुद्धि प्रतिनिधित्व की भावना और आत्मविश्वास का सर्जन कर उनके दृष्टिकोणों का विकास करना है। इस शोधपत्र में द्वितीयक आकड़ों के माध्यम से जो गुणात्मक स्तरों पर आधारित है का प्रयोग किया गया है। शोध पत्र के माध्यम से नई शिक्षा नीति की वास्तविक एवं मूल विशेषताओं को शोधार्थी दर्शाना चाहती है। उपर्युक्त विश्लेषित तथ्यों के आधार पर इस शोधपत्र के माध्यम से अनेक सुझावों को प्रस्तुत चाहती है,। जो भारतीय शिक्षा प्रणाली के लिए अति आवश्यक है। अनादि काल से ही प्रत्येक समाज तथा राष्ट्र अपने नागरिकों को शिक्षित एवं दीक्षित करके स्वयं को विवेक सम्मत समाज बनाने की दशा में निरंतर प्रयासरत है । वर्तमान समय में ज्ञान व कौशल के बदलते स्वरूप से संपूर्ण विश्व तेजी से परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है एवं शिक्षा का क्षेत्र भी परिवर्तित हो रहा है यही कारण है कि देश काल व परिस्थिति के फलस्वरुप शिक्षा की बदलती जरूरतों आकांक्षाओं व व्यवस्थाओं को निरूपित करने के लिए समय समय पर लक्ष्य व मूल्यों पर आधारित शिक्षा नीतियों को प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से परिवर्तित करते रहना चाहिए। वर्तमान समय की शिक्षा तकनीकी एवं नवाचार पर आधारित है जैसे–जैसे तकनीकी विकसित

हो रही है शिक्षा जगत में भी नवाचार दिन प्रतिदिन आता जा रहा है। स्वतंत्र भारत की पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 में घोषित की गई और उन्हें 1986 में भारत सरकार के द्वारा नवीन राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा की गई जिसके अंतर्गत कुछ पक्ष 1992 में परिवर्तित किए गए। जिसको राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का प्लान ऑफ एक्शन कहा जाता है। 34 वर्षों के पश्चात 29 जुलाई 2020 को केंद्रीय सरकार द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का अनुमोदन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया। यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, 21वीं शताब्दी की पहली शिक्षा नीति है जिसका लक्ष्य देश के विकास के लिए अनिवार्य आवश्यकताओं को पूरा करना है एवं राष्ट्र में सभी बच्चों को गुणवत्ता शिक्षा प्रदान करना है। यह नीति भारत की परंपरा और संस्कृति मूल्यों के आधार को बरकरार रखते हुए 21वीं शताब्दी की शिक्षा के लिए आकांक्षात्मक लक्ष्य आवश्यकताओं और विकास के साथ–साथ एसडीजी 4(गुणात्मक शिक्षा) शामिल है तथा सभी पक्षों के सुधार और पुनर्गठन का प्रस्ताव रखती है राष्ट्रीय शिक्षा नीति प्रत्येक व्यक्ति में निहित रचनात्मकता क्षमताओं के विकास पर विशेष जोर देती है यह नीति सिद्धांत पर आधारित है कि शिक्षा से न केवल साक्षरता और संख्या ज्ञान जैसे बुनियादी क्षमता के साथ–साथ उच्चतर स्तर की तार्किक और समस्या समाधान संबंधी संज्ञानात्मक क्षमताओं का विकास होना चाहिए बल्कि नैतिक सामाजिक भावनात्मक स्तर पर भी विकास होना चाहिए।

मूल शब्द: *नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, शिक्षाविदों का योगदान ।*

प्रस्तावना :

एक शिक्षण संस्थान अपने छात्रों को अज्ञानता के अंधेरे से ज्ञान के प्रकाश की ओर ले जाने के लिए सीखने के अनुभव प्रदान करने का एक महत्वपूर्ण कार्य करता है। इस परिवर्तन को लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले संस्थानों में प्रमुख कर्मचारी शिक्षक हैं। जैसा कि एनसीटीई (1998) द्वारा माध्यमिक शिक्षक शिक्षा में गुणवत्ता संगीत कार्यक्रम में कहा गया है, शिक्षक किसी भी शैक्षिक कार्यक्रम में सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। यह शिक्षक है जो किसी भी स्तर पर शैक्षिक प्रक्रिया के कार्यान्वयन के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार है। इससे पता चलता है कि शिक्षकों की तैयारी में निवेश करना अनिवार्य है, ताकि देश का भविष्य सुरक्षित रहे। राष्ट्र की स्कूल प्रणाली के लिए सक्षम शिक्षकों के महत्व को किसी भी तरह से अधिक महत्व नहीं दिया जा सकता है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 शिक्षक पर मांग और अपेक्षाएं रखती है, जिसे प्रारंभिक और सतत शिक्षक शिक्षा दोनों द्वारा संबोधित करने की आवश्यकता है। शिक्षक वास्तव में बच्चों के भविष्य को आकार देते हैं अतः हमारे राष्ट्र के भविष्य का भी निर्माण करते हैं इस योगदान के कारण ही भारत में शिक्षक समाज के सबसे ज्यादा सम्मानित सदस्य हैं और सिर्फ सबसे अच्छे और विद्वान ही शिक्षक बनते हैं विद्यार्थियों को निर्धारित ज्ञान कौशल और नैतिक मूल्य प्रदान करने के लिए समाज शिक्षक को उनके जरूरत की सभी चीजें प्रदान करता है । केंद्रीय शिक्षा मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान ने हमारी भारतीय ज्ञान प्रणाली में इस ऐतिहासिक दिन को संभव बनाने के लिए विशेषज्ञों,शिक्षाविदों और बुद्धिजीवियों की सराहना करते हुए कहा कि एनईपी 2020

पर आधारित भारत का यह शिक्षा मॉडल दुनिया भर में उभरती अर्थव्यवस्थाओं के लिए एक बेंचमार्क के रूप में कार्य करेगा। मोदी सरकार ने 2016 से ही नई शिक्षा नीति लाने की तैयारियां शुरू कर दी थी और इसके लिए टीएसआर सुब्रहमण्यम कमेटी का गठन भी हुआ था, जिन्होंने मई, 2019 में शिक्षा नीति का अपना मसौदा (ड्राफ्ट) केंद्र सरकार के सामने रखा है। लेकिन सरकार को वह ड्राफ्ट अच्छा नहीं आया। इसके बाद सरकार ने वरिष्ठ शिक्षाविद् और जेएनयू के पूर्व चांसलर के– कस्तूरीरंगन की अध्यक्षता में एक नौ सदस्यीय कमेटी का गठन किया।

- महेश चंद्र पंत, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन के चांसलर।
- गोविंद प्रसाद शर्मा, नेशनल बुक ट्रस्ट के चेयरपर्सन।
- टी वी कट्टिमणि, आंध्र प्रदेश के सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी के वीसी।
- मिशेल डैनिनो, आईआईटी गांधीनगर में गेस्ट प्रोफेसर।
- मिलिंद कांबले, चेयरपर्सन आईआईएम, जम्मू ।
- जगबीर सिंह, पंजाब केंद्रीय विश्वविद्यालय के चांसलर, बठिंडा।
- मंजुल भार्गव, भारतीय मूल के अमेरिकी गणितज्ञ।
- एम के श्रीधर, प्रशिक्षक और एक सामाजिक कार्यकर्ता और ड्राफ्ट के लिए एक समिति के सदस्य।
- धीर झिंगरान, के संस्थापक निदेशक लैंग्वेज एंड लर्निंग फाउंडेशन (एलएलएफ) ।
- शंकर मारुवाड़ा, एक स्टेप फाउंडेशन के सह–संस्थापक और सीईओ और एक उद्यमी।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को तैयार करने के लिये विश्व की सबसे बड़ी परामर्श प्रक्रिया आयोजित की गयी थी। विभिन्न शिक्षाविदों के अनुभव तथा के– कस्तूरीरंगन समिति की सिफारिशों के आधार पर शिक्षा तक सबकी आसान पहुँच, समता, गुणवत्ता, वहनीयता और जवाबदेही के आधारभूत स्तंभों पर निर्मित यह नई शिक्षा नीति सतत विकास के लिये एजेंडा 2030 के अनुकूल है और इसका उद्देश्य 21वीं शताब्दी की आवश्यकताओं के अनुकूल स्कूल और कॉलेज की शिक्षा को अधिक समग्र लचीला बनाते हुए भारत को एक ज्ञान आधारित जीवंत समाज और वैश्विक महाशक्ति में बदलकर प्रत्येक छात्र में निहित अद्वितीय क्षमताओं को सामने लाना होगा। नवीन शिक्षा नीति 2020 नीति के अनुसार शिक्षा पूर्ण मानव क्षमता प्राप्त करने, एक न्यायसंगत और न्यायपूर्ण समाज के विकास और राष्ट्रीय विकास को बढ़ावा देने के लिए मौलिक है।

गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए सार्वभौमिक पहुँच प्रदान करना आर्थिक वृद्धि, सामाजिक न्याय और समानता, वैज्ञानिक उन्नति, राष्ट्रीय एकीकरण और सांस्कृतिक संरक्षण के संदर्भ में वैश्विक मंच पर भारत के निरंतर चढ़ाई और नेतृत्व की कुंजी है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति तैयार करने में शिक्षाविदों के साथ–साथ अभिभावकों एवं अन्य शिक्षा संबंधी व्यक्तियों ने अपना अपना योगदान अपने स्तर से किया है शिक्षाविदों का योगदान अति आवश्यक था क्योंकि वह वर्तमान समय की शिक्षा संबंधी आवश्यकताओं को समझते हैं बालकों की आवश्यकताओं को समझते हैं तथा बालको को भावी जीवन में आने वाली कठिनाइयों से अवगत कराने में सक्षम है। शिक्षाविदों का मानना है कि अध्यापक शिक्षा की गुणवत्ता भर्ती पद स्थानांतरण सेवा शर्त और शिक्षकों के अधिकार की स्थिति वैसे नहीं है जैसे होनी चाहिए और इसके परिणाम स्वरूप शिक्षकों की गुणवत्ता और उत्साह अवांछित मांगों का प्राप्त नहीं कर पाता है शिक्षकों के लिए उच्चतर दर्जा और उसके प्रति आदर और सम्मान के भाव को पुनर्जीवित करना होगा ताकि शिक्षण व्यवसाय में 72 लोगों को शामिल करने हेतु उन्हें प्रेरित किया जा सके। हमारे छात्रों और हमारे राष्ट्र के लिए सर्वोत्तम संभव भविष्य सुनिश्चित करने के लिए शिक्षकों की प्रेरणा और सशक्तिकरण बहुत आवश्यक है। शिक्षक और समुदाय के बीच एक अच्छा संबंध होना चाहिए और शिक्षक समुदाय से जुड़ा रहे जिससे विद्यार्थियों को रोल मॉडल और शैक्षिक वातावरण मिल सके इससे यह सुनिश्चित करने में लाभ मिलेगा की शिक्षक स्थानांतरण की हानिकारक प्रैक्टिस इस पर रोक लगाई जाएगी केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा यह निर्धारित किया जाएगा कि स्थानांतरण किन परिस्थितियों में किया जाएगा इसके अलावा स्थानांतरण में पारदर्शिता किस प्रकार बनाई जाएगी एवं ऑनलाइन सॉफ्टवेयर आधारित स्थानांतरण किया जाएगा। जिससे कुछ हद तक भ्रष्टाचार को भी कम किया जा सकेगा।

वर्तमान समय की आवश्यकता को देखते हुए शिक्षा शास्त्रियों ने पाठ्यक्रम में विज्ञान एवं तकनीकी,चरित्र विकास एवं मानवीय मूल्यों को अधिक महत्व दिया है एवं कहां की पाठ्यक्रम को इस प्रकार से डिजाइन किया जाना चाहिए जिससे शिक्षा को कौशल व्यवसायिक प्रशिक्षण एवं इंडस्ट्री इंटरफेस के साथ एकीकृत कर सकें एवं भारतीय शिक्षा संस्थानों द्वारा छात्रों को अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप ज्ञान कौशल और क्षमता प्रदान की जा सके छात्रों को वैश्विक नागरिक के रूप में अपनी प्रासंगिकता बढ़ाने वाले वैश्विक दृष्टिकोण को विकसित करने में यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति सहायक सिद्ध हो। खोई हुई विश्वसनीयता को पुनः प्राप्त करने और विश्वविद्यालय, महाविद्यालय एवं स्कूल की क्षमता बढ़ाने के लिए अधिगम परिणामों नियोजन का संबंधी कौशल और दक्ष ताऊ पर ध्यान केंद्रित करने के साथ राष्ट्रीय शिक्षा योग्यता फ्रेमवर्क को अपग्रेड किया जाना चाहिए।

स्कूली शिक्षा में शिक्षाविदों का योगदान :

भारत में प्राथमिक शिक्षा का तात्पर्य कक्षा 1 से 8 तक की शिक्षा से है इसके विकास का अर्थ समय के साथ शादी में होने वाले मात्रात्मक प्रगति और गुणात्मक उन्नयन से है यदि हम प्राथमिक शिक्षा के स्तर

पर सार्वभौमिक नामांकन की बात करें तो वर्ष 2015–16 से वर्ष दो हजार अट्ठारह उन्नीस के आंकड़ों में काफी अंतर देखने को मिलता है। कुछ राज्यों में प्राथमिक शिक्षा में नामांकन दर स्थिर रही परंतु संपूर्ण भारत के संदर्भ में इसमें कमी परिलक्षित हो रही हैं। वर्तमान में शिक्षा में गुणवत्ता को देखते हुए प्राथमिक स्तर पर दी जाने वाली शिक्षा में भी एक बड़ी कमी शिक्षा के गुणवत्ता के निर्धारण किए जाने के संबंध में देखने को आती है पूर्ण पूर्ण शिक्षा हेतु जहां विद्यालय में कुछ सुविधाएं जैसे पुस्तकालय, शिक्षण अधिगम सामग्री व अन्य चीजों की आवश्यकता होती है इसे देखते हुए विद्यालय में संसाधनों का अभाव है इन अभाव को देखते हुए शिक्षाविदों ने प्राथमिक शिक्षा के लिए अनेक सुझाव दिए जिसके अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण सुझाव निम्न वत है।

- वर्तमान की शिक्षा नीति 10̣ 2 वाली स्कूली शिक्षा को 3 से 18 वर्ष के सभी वर्गों के लिए पाठ्यचर्या और शिक्षण शास्त्रीय आधार पर 5+3+3+4 की एक नई व्यवस्था में पुनर्गठित करने की बात करते हैं । 5 को फाउंडेशन स्टेज कहां गया जिसके अंतर्गत आंगनवाडी बालवाड़ी 3 वर्ष की शिक्षा तथा कक्षा 1 और 2 को शामिल किया जाएगा पहले 3 को प्रिपेरेटरी स्टेज कहा जिसके अंतर्गत कक्षा 3 से 8 तक की शिक्षा को शामिल किया गया जायेगा दूसरे 3 को मिडिल स्टेज कहा जिसके अंतर्गत कक्षा 6 से 8 तक की शिक्षा को शामिल किया जाएगा चार को सेकेंडरी स्टेज कहा गया है जिसके अंतर्गत कक्षा 9 से 12 तक की शिक्षा को शामिल किया जाना चाहिए

- एनसीईआरटी के द्वारा प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या और शिक्षण शास्त्र तैयार किया जाना चाहिए जिससे पूर्व प्राथमिक एवं प्राथमिक शिक्षा को एक नया मोड़ दिया जा सके।

- शिक्षाशास्त्रियों ने 10 दिन बस्ता रहित स्कूल आने की वकालत की है इससे उनका अभिप्राय बालकों को स्कूल में स्थानीय व्यवसाय, कौशल एवं विशेषज्ञों से परिचित करा कर दैनिक जीवन कोशलो से अवगत कराना है।

- शिक्षाशास्त्रियों का मानना है कि स्कूल में बच्चों का ड्रॉप आउट रेट ज्यादा होता है जिसको कम करने के लिए हमें लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए जिसके लिए न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत यह लक्ष्य 2030 तक 100 प्रतिशत सकल नामांकन अनुपात का रखा गया है ।

- NCERT राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा स्कूली शिक्षा के लिए 2020–21 तक तैयार करेंगी।

- शिक्षा शास्त्रियों के अनुसार मूल्यांकन प्रक्रिया में भी कुछ परिवर्तन किया गया जिसके अंतर्गत न्यू एजुकेशन पॉलिसी में PARAKH (समग्र विकास के लिए प्रदर्शन आकलन समीक्षा और ज्ञान का विश्लेषण) एमएचआरडी के द्वारा बनाया जाएगा जिसको नेशनल एसेसमेंट सेंटर का नाम दिया गया।

- एसडी 4 को ध्यान में रखते हुए सभी को समावेशी समान गुणवत्ता युक्त जीवन पर्यंत शिक्षा के अवसर को बढ़ावा दिया जाने का लक्ष्य 2030 तक रखा जाना चाहिए।

- 2025 तक प्राथमिक विद्यालय में सार्वभौमिक मूलभूत साक्षरता और संख्या ज्ञान प्रदान करना अनिवार्य होगा।

- त्रिभाषा सूत्र को जारी रखा जाएगा हालांकि 3 भाषा के इस फार्मूले में काफी लचीलापन रखा जाएगा और किसी भी राज्य पर कोई भाषा टोपी नहीं जाएगी।

- गुणवत्ता मानकों के अनुपालन में नमन एवं मान्यता प्रणाली के लिए एस एस एस ए (राज्य स्कूल मानक प्राधिकरण) नामक स्वतंत्र राज्य निकाय का निर्माण किया जाएगा जो बुनियादी मानकों की स्थापना करेगा।

- स्कूल विनियमन, प्रमाण पत्र और गवर्नमेंट के लिए मानक ढांचे और शुभम प्रणाली की समीक्षा की जाएगी ताकि पिछले दशक से प्राप्त की गई थी और अनुभव के आधार पर सुधार किया जा सके शिक्षा का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना होगा कि सभी छात्र विशेष रूप से सुविधाओं से वंचित तबकों के छात्रों को उच्च गुणवत्ता और समानता पूर्वक शिक्षा प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा से लेकर उच्च माध्यमिक शिक्षा निशुल्क एवं अनिवार्य हो।

उच्च शिक्षा एवं शिक्षविदो का योगदानः

शिक्षाविदों का मानना है कि यह नीति ग्रामीण और शहरी भारत दोनों में प्राथमिक शिक्षा से उच्च शिक्षा के साथ–साथ व्यावसायिक प्रशिक्षण में परिवर्तनकाल के लिए एक व्यापक ढांचा है। इस नीति का उद्देश्य 2030 तक भारत की शिक्षा प्रणाली को बदलना है। नई शिक्षा नीति को स्कूल स्तर से विश्वविद्यालय स्तर तक प्रणाली में औपचारिक परिवर्तनों को औपचारिक रूप देने के उद्देश्य से पेश किया गया है। बदलते परिदृश्य को ध्यान में रखते हुए, अब से शैक्षिक सामग्री प्रमुख अवधारणाओं, विचारों, अनुप्रयोगों और समस्या समाधान के कोणों पर ध्यान केंद्रित करेगी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति से देश की उच्च शिक्षा प्रणाली पर सकारात्मक और दीर्घकालिक प्रभाव पड़ने की उम्मीद है। यह तथ्य कि विदेशी विश्वविद्यालयों को भारत में परिसर खोलने की अनुमति है, सरकार की एक सराहनीय पहल है। इससे छात्रों को अपने देश में शिक्षा की समग्र गुणवत्ता का अनुभव करने में मदद मिलेगी। बहु–विषयक संस्थान शुरू करने की नीति कला, मानविकी जैसे सभी क्षेत्रों में नए सिरे से ध्यान केंद्रित करेगी और शिक्षा के इस रूप से छात्रों को सीखने और समग्र रूप से विकसित होने में मदद मिलेगी।उच्च शिक्षा के क्षेत्र में 2030 तक सकल नामांकन अनुपात (जीईआर) को मौजूदा 26 प्रतिशत से बढ़ाकर 50 प्रतिशत करने के लिए एनईपी 2020 की कल्पना की गई थी। इसका उद्देश्य मुक्त और दूरस्थ शिक्षा, ऑनलाइन शिक्षा और शिक्षा में प्रौद्योगिकी के उपयोग को बढ़ाने के लिए बुनियादी ढांचे

को मजबूत करके छात्रों के समग्र व्यक्तित्व का निर्माण करना है। इसके अलावा, देश में अनुसंधान कार्य को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन (एनआरएफ) की स्थापना की जाएगी। देश भर में उच्च शिक्षा संस्थानों के लिए एकल नियामक के रूप में परिकल्पित एक राष्ट्रीय प्रत्यायन परिषद (एनएसी) की स्थापना की जाएगी। भारतीय उच्च शिक्षा परिषद (एचईसीआई) में विभिन्न भूमिकाओं को पूरा करने के लिए कई कार्यक्षेत्र होंगे। सभी सरकारी भर्ती परीक्षाओं के लिए एक राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी और समान स्तर की विभिन्न भर्ती परीक्षाओं के लिए एक सामान्य पात्रता परीक्षा (सीईटी) स्थापित करने के प्रयास किए जाएंगे। इसके साथ ही विषयों में पाठ्यक्रम और कार्यक्रम, जैसे कि इंडोलॉजी, भारतीय भाषाएं, चिकित्सा की आयुष प्रणाली, योग, कला, संगीत, इतिहास, संस्कृति और आधुनिक भारत, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और उससे आगे के अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रासंगिक पाठ्यक्रम, सार्थक अवसर वैश्विक गुणवत्ता मानकों के इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सामाजिक जुड़ाव, गुणवत्ता आवासीय सुविधाओं और परिसर में समर्थन आदि को बढ़ावा दिया जाएगा।

उपसंहार :

वर्तमान में हमारे देश में शिक्षा के उद्देश्य से निश्चित एवं स्पष्ट है और उसकी आधारभूत पाठ्यचर्या का निर्माण भी कर दिया गया है और किया जा रहा है यह बात दूसरी है कि समय की मांग के अनुसार इस में परिवर्तन दिन–ब–दिन करते जा रहे हैं वर्तमान में शिक्षा के क्षेत्र में सबसे बड़ी समस्या इस के सार्वभौमीकरण की है सरकारी आंकड़े बताते हैं कि इतने प्रयासों के बाद भी आंकड़ों में खासा बदलाव नहीं है । इस संदर्भ में चिंता का दूसरा विषय यह है कि अनेक उपाय करने के बाद भी वर्तमान में कक्षा 1 से 8 तक लगभग 30% और अवरोधन लगभग 20% हो रहा है। नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार शिक्षा रटने वाले विषयों, समय सीमा को पूरा करने और अंक प्राप्त करने से कहीं स्तर पर है, लेकिन शिक्षा का वास्तविक अर्थ ज्ञान, कौशल, मूल्यों को प्राप्त करना और उस क्षेत्र में निरंतर कार्य करना और प्रगति करना है, जिसमें व्यक्ति अपनी रुचि खोज की करता है। इसमें कोई सन्देह नहीं कि अगर नई शिक्षा नीति 2020 को सही तरीके से लागू किया जाए तो यह भारतीय शिक्षा को नई ऊंचाइयों पर ले जा सकती है। हालाँकि इसके कुछ उद्देश्यों एवं लक्ष्यों की स्पष्टता का अभाव है, लेकिन हम वास्तव में इसका न्याय तब तक नहीं कर सकते जब तक कि इसकी लिखित योजनाएँ क्रिया में न आ जाएँ हम केवल सर्वोत्तम परिणामों की आशा कर सकते हैं, आखिरकार, यह छात्रों के समग्र विकास और प्रगति को नई ऊंचाइयों तक ले कर जाएगी। नई शिक्षा नीति रूढ़िवादिता परंपरागत शिक्षण विधि एवं कठिनाइयों को समाप्त कर देश को अधिक गतिशील एवं परिवर्तनशील बनाएगी।

संदर्भ ग्रंथ :

1. https://www.lisworld.-in/p/new-education-policy-and-library-by-html
2. नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति ड्राफ्ट 2020
3. https://link-springer-com.translate.goog/article/10.1007/s10734 -020-00565-8?error= cookies_not_supported&code=e9b0bbe6= 9704=4212=9866=8d1bcd54319e&_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=hi&_x_tr_hl=hi& _x_tr_pto=tc,sc
4. Kumar, K. (2005), Quality of Education at the Beginning of the 21st Century: Lessons from India. Indian Educational Review 2. Draft National Education Policy 2019.
5. https://innovate.mygov.in.wpcontent.uploads/2019/06/mygov 15596510111.pdf 3. National Education Policy 2020.
6. https://www.mhrd.gov.-in/sites/upload_files/mhrd/files/nep/ NEP_Final_English.pdf referred 10/08/2020

THE RESEARCH DIALOGUE

An Online Quarterly Multi-Disciplinary
Peer-Reviewed / Refereed Research Journal
ISSN: 2583-438X
Volume-2, Issue-1, April-2023
www.theresearchdialogue.com
Certificate Number-April-2023/24

Certificate Of Publication

This Certificate is proudly presented to

कवता विश्नोई

for publication of research paper title

राष्ट्रीय नई शिक्षा नीति 2020 और शिक्षाविदों का योगदान

Published in 'The Research Dialogue' Peer-Reviewed / Refereed Research Journal and E-ISSN: 2583-438X, Volume-02, Issue-01, Month April, Year-2023.

Dr.Neeraj Yadav
Executive Chief Editor

Dr.Lohans Kumar Kalyani
Editor-in-chief

Note: This E-Certificate is valid with published paper and the paper must be available online at www.theresearchdialogue.com